B.A Part I
IInd paper

लचीली मजदूरी बनाम लचीली मौद्रिक नीति :-
(Flexible wage policy vs Flexible monetary policy)

केन्ज़ क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की इस बात से सहमत नहीं था कि लचीली मजदूरी नीति से पूर्ण रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। वह लचीली मजदूरी नीति से की अपेक्षा लचीली मौद्रिक नीति के पक्ष में था क्योंकि लचीली मजदूरी नीति में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां विद्यमान थीं। इस विषय में केन्ज़ के मत की परिचर्चा करने के लिए क्लासिकी दृष्टिकोण का संक्षेप में वर्णन करते हैं।

क्लासिकी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार विद्यमान रहता है। बेरोजगारी का कारण मजदूरी का अलचीलापन (~~rigidity~~) (rigidity) है। इसलिए मुद्रा मजदूरी में सामान्य कटौती करने से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच जाएगी। क्लासिकियों का तर्क यह है कि प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में मुद्रा मजदूरी में कटौती करने से उत्पादन की लागत तथा कीमतें गिर जाएंगी। कीमतें गिरने से वस्तुओं की मांग और विक्रय बढ़ जाएंगे, जिससे आवश्यक हो जाएगा कि अधिक श्रम को रोजगार पर लगाया जाए। यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को अन्ततः पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचा देगी। क्लासिकी तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा मजदूरी दर में होने वाला परिवर्तन वास्तविक मजदूरी से प्रत्यक्ष और स्वं समानुपातिक रूप से संबंध रहता है। इसलिए जब मुद्रा मजदूरी घटती है तो वास्तविक मजदूरी भी उसी सीमा तक घट जाती है।

केन्ज क्लासिकियों के इस तर्क से सहमत नहीं था कि पूर्ण रोजगार उपलब्ध करने के लिए मुद्रा मजदूरी में कटौती करना जरूरी है। उसने मुद्रा मजदूरी की निम्नगामी लचीलापन

Scanned by CamScanner

(downward flexibility) की नीति का निम्नलिखित कारणों से विरोध किया –

1. केन्ज़ के मतानुसार, मुद्रा मजदूरी में सामान्य कटौती रोजगार को बढ़ाने की बजाय कम करती है। मुद्रा मजदूरी में कटौती होने से वर्करों की मुद्रा आय कम हो जाती है और वे अपनी वस्तुओं की मांग घटा देते हैं। इससे समस्त मांग, उत्पादन और रोजगार घट जाएंगे।

2. फिर, जब केवल वर्करों की मजदूरी घटाई जाती है तो गैर - मजदूरी अर्जकों (earners) की तुलना में उनकी आय कम हो जाती है। क्योंकि वर्करों की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति अधिक है और गैर - मजदूरी अर्जकों की कम, इसलिए समस्त उपभोग घट जाएगा। इससे समस्त मांग, उत्पादन और रोजगार घट जाएंगे।

3. फिर यह भी निश्चित है कि मुद्रा मजदूरी में सामान्य कटौती का अर्थव्यवस्था में पूंजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC), निवेश तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि व्यापारी यह आशा करते हैं कि मजदूरी कटौती से मजदूरी ~~मिलेगी~~ और गिरेगी तो MEC गिर जाएगी और व्यापारी अपनी निवेश योजनाओं को स्थगित कर देंगे। इससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर, यदि ट्रेड यूनियनों हड़ताल करके मुद्रा मजदूरी दर में कटौती का विरोध करेंगी, तो फिर MEC गिरेगी। इसका कारण यह है कि श्रम असंतोष के परिणामस्वरूप व्यापार प्रत्याशाओं और MEC में गिरावट आएगी। इस तरह की परिस्थितियों में व्यापारी निवेश करने से झिझकेंगे, जिससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. कुछ व्यावहारिक कारणों से भी केन्ज़ मुद्रा मजदूरी में कटौती ~~का अर्थ~~ के रूप में लचीली मजदूरी नीति के पक्ष में ~~में~~ नहीं था। उसके मतानुसार, ट्रेड यूनियनों इस तरह की नीति का

Scanned by CamScanner

विरोध करेंगी। वे मुद्रा मजदूरी में सभी और कटौती स्वीकार नहीं करेंगी। प्रजातन्त्रात्मक देशों में, जहाँ सामूहिक सौदेबाजी करने की इजाजत होती है, मुद्रा मजदूरी में कटौती एक अव्यावहारिक संभावना है। इसलिए लचीली मजदूरी नीति की अपेक्षा लचीली मौद्रिक नीति का अनुसरण करना बहुत आसान है।

5. फिर सामाजिक न्याय की माँग है कि केवल वर्करों की मुद्रा मजदूरी न घटाई जाए। यदि वर्करों की मुद्रा मजदूरी में कटौती की जाएगी, जबकि समुदाय के अन्य वर्गों की आय अपरिवर्तित रहेगी, तो अन्य वर्गों की तुलना में वर्करों का जीवन-स्तर गिर जाएगा। सामाजिक न्याय की माँग है कि समाज के सब वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाए और मुद्रा मजदूरी में कटौती के कारण केवल वर्करों को कष्ट न भोगना पड़े। यही कारण है कि केन्ज़ मन्दी के दौरान मुद्रा मजदूरी में कटौती की नीति की अपेक्षा मुद्रा पूर्ति बढ़ाने की नीति को अधिमान देता है क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे (मुद्रा पूर्ति बढ़ाने की नीति से) सब वर्गों की वास्तविक आय प्रभावित होगी।

6. अंतिम बात, जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं, यह है कि मुद्रा मजदूरी में कटौती करने के कारण कीमतें गिरती हैं तो वह कर्जदारों पर कर्जे का वास्तविक बोझ बढ़ जाता है। क्योंकि अधिकांश कर्जदार व्यापारी होते हैं इसलिए इस तरह की नीति का व्यापार प्रत्याशाओं, MEC निवेश, उत्पादन तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की नीति कर्जे का बोझ कम करेगी, क्योंकि वह कीमत स्तर को बढ़ाएगी।

Scanned by CamScanner